संसद में धक्का-मुक्की, दो सांसद चोटिल

भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई थाने में शिकायत

अर्चिस मोहन

भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चार बैठकों में 32 घंटे और 51 मिनट बहस हुई, जिसमें लोक सभा में 136 और राज्य सभा में 73 यानी कुल 209 सांसदों ने हिस्सा लिया और संविधान के वास्तुकार भीमराव आंबेडकर की विरासत को संरक्षित करने की बात कही। दोनों सदनों में गरमा-गर्म बहस के बावजूद पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने धैर्यपूर्वक इसे सुना। लेकिन, गुरुवार को नजारा उस समय बदल गया जब संसद भवन परिसर में सांसद एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने लगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक-दूसरे की महिला सांसदों के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगाए और दिन में संसद भवन परिसर ऐसे नजारे का गवाह बना जो पहले कभी नहीं देखा गया था।

नागालैंड से भाजपा की राज्य सभा सांसद एस फंगनोन कोन्याक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का-मुक्की में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने, उकसाने जैसे आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज करने की मांग की है।

कांग्रेस ने भी राजधानी के संसद मार्ग थाने में शिकायत दी है और भाजपा नेताओं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने बताया कि दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी सहित कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने थाने में जाकर शिकायत सौंपी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तिवारी ने पुलिस थाने के बाहर मीडिया से कहा, '84 वर्षीय दलित नेता मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।' मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस सदस्यों को मकर द्वार पर संसद में प्रवेश करने से रोका। इस दौरान उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर बैठ गए। कांग्रेस के सांसद आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर संसद भवन की तरफ लौट रहे थे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की।

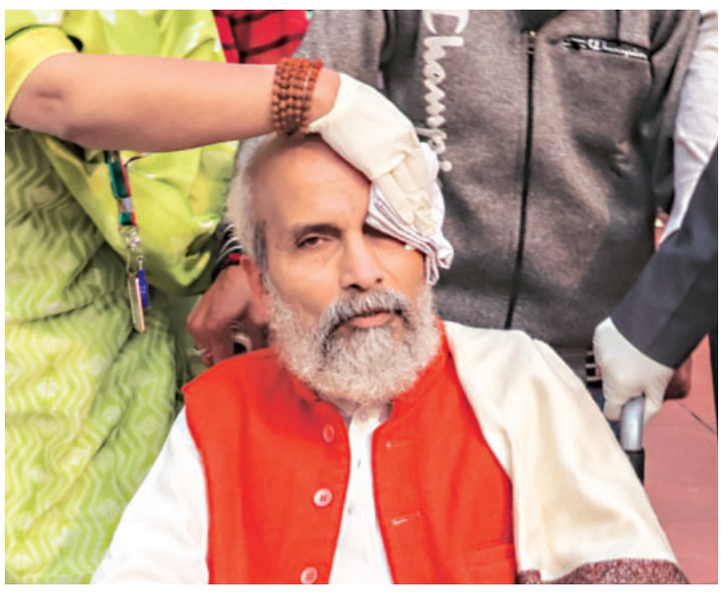

संसद परिसर में धक्का- मुक्की के बाद घायल हुए भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी

बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा उन पर दुर्व्यवहार के आरोप इसलिए लगा रही है ताकि शीतकालीन सत्र में कांग्रेस द्वारा उठाए गए अदाणी मामले और आंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगने के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। इन मुद्दों पर भाजपा ने संसद में भी चर्चा की इजाजत नहीं दी। खरगे के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राहुल ने कहा, 'भाजपा और आरएसएस की सोच संविधान और आंबेडकर विरोधी है। ये लोग आंबेडकर की स्मृति और योगदान को मिटाना चाहते हैं।' खरगे ने कहा कि आंबेडकर के अपमान के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में अभियान चलाएगी।

दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष के विरोध प्रदर्शन में जानबूझ कर पहुंचने और धक्कामुक्की के साथ-साथ 'गुंडागर्दी' करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके जैसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरुवार को संसद परिसर में अशोभनीय और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार किया गया, जिसकी सभ्य समाज कल्पना भी नहीं कर सकता। चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार के कारण 'हमारे बुजुर्ग, गरीब और शालीन' सांसद प्रताप सारंगी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। बालासोर के सांसद 69 वर्षीय सारंगी के सिर में टांके लगे हैं। दूसरे सांसद राजपूत को सिर में चोट आई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके भाई और सांसद राहुल गांधी अन्य सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें भाजपा सांसदों ने संसद में प्रवेश करने से रोका। भाजपा सांसदों ने उन्हें और राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। भाजपा और कांग्रेस ने लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा में सभापति को भी एक-दूसरे के खिलाफ अपनी-अपनी शिकायतें दी हैं।

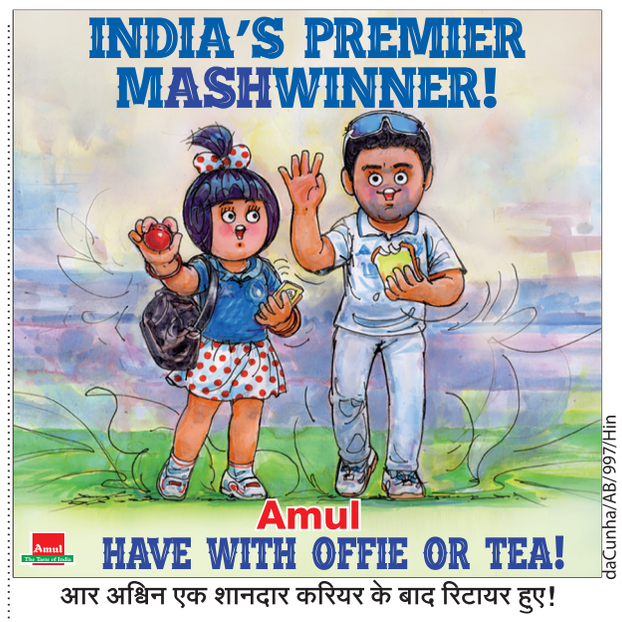

आर अश्विन एक शानदार करियर के बाद रिटायर हुए!

धनखड़ को पद से हटाने की मांग

हरिवंश ने नोटिस को किया खारिज

राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को विपक्ष का वह नोटिस खारिज कर दिया जिसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संचालन का आरोप लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। राज्य सभा के महासचिव पी सी मोदी ने उच्च सदन में यह घोषणा की। महासचिव मोदी ने उपसभापति द्वारा दी गई इस व्यवस्था की प्रति सदन के पटल पर रखी।

जगदीप धनखड़, सभापति

उप सभापति ने धनखड़ के खिलाफ नोटिस को अनुचित और त्रुटिपूर्ण करार दिया और कहा कि इसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राज्य सभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है।

उल्लेखनीय है कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नैशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दलों ने सभापति धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस 10 दिसंबर को राज्य सभा के महासचिव को सौंपा था। विपक्षी सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के इरादे से नोटिस दिया था। विपक्ष ने कहा था कि धनखड़ द्वारा 'अत्यंत पक्षपातपूर्ण' तरीके से राज्य सभा की कार्रवाई संचालित करने के कारण यह कदम उठाना पड़ा है।

सूत्रों के मुताबिक उपसभापति ने फैसला सुनाया कि 'व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के मकसद से लाए गए' नोटिस की गंभीरता तथ्यों से परे है और प्रचार हासिल करने के उद्देश्य से है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस सबसे बड़े लोकतंत्र के उपराष्ट्रपति के उच्च संवैधानिक पद को जानबूझकर महत्त्वहीन बनाने और अपमानित करने का एक 'दुस्साहस' है। सूत्रों ने कहा कि संसद और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए चिंताजनक बात है कि नोटिस में ऐसे दावे भरे पड़े हैं जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि को खराब करने के लिए हैं। उपसभापति ने अपने फैसले में कहा कि नोटिस में अनुच्छेद 67 (बी) का आह्वान किया गया है, जो उपराष्ट्रपति को हटाने पर विचार करने वाले किसी भी प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य करता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार 10 दिसंबर, 2024 का दिया गया नोटिस 24 दिसंबर, 2024 के बाद ही कुछ हो सकता था।

उप सभापति ने अपने फैसले में कहा कि इस सत्र के दौरान प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वर्तमान सत्र 20 दिसंबर तक ही प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को पूरी तरह से जानते हुए भी केवल दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद और उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक विमर्श स्थापित करने के लिए यह सब किया गया। हरिवंश ने यह भी कहा कि नोटिस में 'नेकनीयती की कमी' है और बाद की घटनाओं से पता चलता है कि 'यह प्रचार पाने का एक सोचा-समझा प्रयास था।

सूत्रों ने कहा कि उपसभापति ने यह भी फैसला सुनाया है कि पूर्वाग्रही इरादा एक समन्वित मीडिया अभियान के आयोजन के माध्यम से प्रकट हुआ, जिसमें 12 दिसंबर, 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल के नेता और मुख्य सचेतक द्वारा शुरू की गई एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। **भाषा**

बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर

भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है। राज्य सभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह का यह जवाब, विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ढाका की यात्रा करने और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शीर्ष राजनीतिक अधिकारियों को इस मामले पर नई दिल्ली की चिंताओं से अवगत कराने के कुछ दिनों बाद आया है।

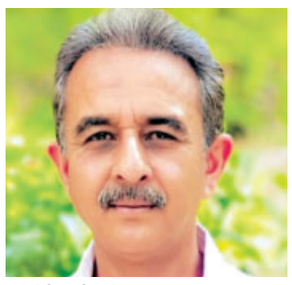

कीर्ति वर्धन सिंह

उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि उस देश की सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के संबंध में कथित तौर पर 70 लोगों को गिरफ्तार किया है और 88 मामले दर्ज किए हैं। सिंह ने कहा, 'बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भारत की चिंताओं को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अधिकारियों के समक्ष विभिन्न अवसरों पर, उच्चतम स्तर पर भी, उठाया गया और दोहराया गया है।' मंत्री ने बांग्लादेश की स्थिति पर अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, 'ढाका में भारत का उच्चायोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है।' **भाषा**

जितनी देर पिक्चर देखें बस उतना ही पैसा दें

रोशनी शेखर

भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर थियेटर में 'फ्लेक्सी शो' मॉडल की पेशकश करने जा रही है। इस मॉडल के तहत दर्शकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जो देखेंगे उसी के लिए ही उन्हें भुगतान करना होगा। यानी दर्शकों को यह छूट होगी कि वे सिनेमा देखने के दौरान किसी भी वक्त वहां से निकल सकेंगे और उतने ही समय के लिए उन्हें भुगतान करना होगा जितनी देर उन्होंने फिल्म देखी है।

पीवीआर आइनॉक्स के मुख्य कार्य अधिकारी (लक्जरी कलेक्शन और नवाचार) रेनॉड पैलियर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि मनोरंजन कंपनी के तौर पर उनके लिए यह लाजिमी है कि वे जिस तरह की सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं, उसमें कुछ नयापन लाया जाए और इसकी वजह से ही फ्लेक्सी शो जैसी नई सेवा देने के बारे में सोचा जा रहा है। फिलहाल मल्टीप्लेक्स चेन इसका प्रायोगिक परीक्षण कर रही है और दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम में चुनिंदा फिल्मों के कुछ शो के लिए 'फ्लेक्सी शो' का विकल्प है।

पीवीआर आइनॉक्स प्रीमियम स्क्रीन को देगी बढ़ावा

- पीवीआर आइनॉक्स ने अब 4डीएक्स, आईमैक्स और आईस जैसे प्रीमियम प्रारुप वाले स्क्रीन की पेशकश करने का लक्ष्य तय किया है ताकि थियेटर में सिनेमा देखने वाले दर्शकों को दूसरी दुनिया में जाने का अहसास हो
- हाल में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'वेनमः दि लास्ट डांस' आईमैक्स में रिलीज हुई थी, 'ग्लैडिएटर 2' आईमैक्स और आईस फॉर्मेट में तथा 'मोआना 2' भी प्रीमियम फॉर्मेट में ही रिलीज की गई

पैलियर ने बताया, 'हम इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि एआई वाला वीडियो एनालिटिक्स और यह निगरानी करेंगे कि ऑडिटोरियम में कौन बैठा है। टिकट आपकी (दर्शक) सीट से लिंक किया गया होगा, ऐसे में सिस्टम को पता चल जाएगा कि आप कब आए और कब निकल गए। सिस्टम इसकी गणना भी करेगा कि आपने कितनी देर फिल्म देखी है और पहले से तय किए गए ब्रैकेट के हिसाब से ही आपका रिफंड तय होगा।'

रिफंड की गणना फिल्म को बीच में छोड़कर जाने के समय के हिसाब से तय होगी। मिसाल के तौर पर अगर आधी फिल्म अभी बाकी है तब दर्शक को 50 प्रतिशत रिफंड मिलेगा और अगर 25-50 प्रतिशत फिल्म बाकी है तब 30 प्रतिशत रिफंड मिलेगा। अगर फिल्म आधी से अधिक बाकी है तब दर्शक को 60 प्रतिशत रिफंड मिलेगा।

पैलियर कहते हैं, 'इसके जरिये हम दर्शकों के आधार में विस्तार कर रहे हैं और इसके चलते वही दर्शक फिर से दोबारा आ सकते हैं क्योंकि इस तरह के विकल्प से लोगों को महसूस हो सकता है कि वे एक शो को कई बार देख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार फिल्में देखकर आनंद उठा सकते हैं।' उन्होंने कहा कि इस तरह की सेवाओं की पेशकश महानगरों में की जाएगी।

बुजुर्ग होते भारत पर भूलने की बीमारी का बढ़ता खतरा

वर्ष 2050 तक भारत में विश्व की 15 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग आबादी होगी

अनीका चटर्जी

भारत में वर्ष 2050 तक विश्व की 15 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग आबादी हो जाएगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के बीच विशेषज्ञों ने चेताया है कि देश में डिमेंशिया (स्मृतिलोप या भूलने की बीमारी) का खतरा बढ़ सकता है। इस समय 60 साल और अधिक उम्र के करीब 7.4 प्रतिशत भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित हैं। यहां अभी डिमेंशिया के मरीजों की संख्या 88 लाख है। यह आंकड़ा वर्ष 2036 तक 97 प्रतिशत बढ़ कर 1.7 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।

भारतीय अल्जाइमर एवं संबंधित विकार सोसायटी के अनुसार वर्ष 2010 में देश में इस बीमारी के 37 लाख मरीज थे, जिनके 2030 तक दोगुने तक बढ़ने का अनुमान है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस रोग की गिरफ्त में 30 से 50 आयु वर्ग के लोग भी आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अल्जाइमर पीड़ित लोगों में 5 से 10 प्रतिशत भारत में है। अल्जाइमर होने के प्रमुख कारक वंशानुगत, जीवनशैली और एक साथ दो बीमारियां जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप होना है।

भारत में बड़ी उम्र के लोगों की आबादी नाटकीय रूप से बढ़ेगी। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक देश की करीब 20 प्रतिशत जनसंख्या की उम्र 60 या उससे अधिक होगी। उस समय तक बुजुर्गों लोगों की कुल संख्या 31.9 करोड़ पहुंच सकती है। विश्व की वृद्ध आबादी में भारत की हिस्सेदारी करीब 15.4 प्रतिशत हो जाएगी। इस उम्र में डिमेंशिया का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसे देखते हुए इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या में बहुत अधिक इजाफा हो सकता है।

डिमेंशिया इंडिया अलायंस के कार्यकारी निदेशक रमानी सुंदरम के अनुसार न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों के फैलने के लिए सबसे बड़ा कारक आयु होती है। अल्जाइमर आमतौर पर 65 वर्ष की आयु के बाद होता है। हालांकि कुछ मामलों में 30 से 60 वर्ष आयु के बीच भी यह बीमारी जकड़ लेती है। हंटिंगटन जैसी बीमारी जैसी स्थितियां 30 से 50 की आयु में भी उभर सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ डिमेंशिया का खतरा बढ़ता जाता है और 85 वर्ष की आयु तक 3 में से एक बुजुर्ग इससे प्रभावित हो जाता है।

सुंदरम ने बताया, 'भारत में डिमेंशिया होने के प्रमुख कारक जनसांख्यिकीय परिवर्तन, शहरीकरण, खानपान की आदतों के साथ-साथ आनुवांशिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा, यहां धड़ल्ले से तंबाकू और शराब का सेवन होता है। डिमेंशिया के ज्यादातर मामलों में प्रारंभिक शुरुआत 65 वर्ष के बाद होती है। बुढ़ापे से पहले डिमेंशिया होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी आयु वर्ग के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।'

पटपड़गंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरोसाइंसेज, न्यूरोलॉजी विभाग के प्रधान निदेशक विवेक कुमार के अनुसार, 'उम्र बढ़ने के साथ डिमेंशया की गिरफ्त में आने का खतरा बढ़ जाता है। मोटे तौर पर 65 वर्ष की आयु के बाद हर पांच साल में डिमेंशिया होने का खतरा दोगुना हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 65 से 69 आयु वर्ग में हर 100 में से 2 लोगों को डिमेंशिया होता है। हालांकि डिमेंशिया युवा उम्र में भी हो सकता है। डिमेंशिया के 9 प्रतिशत तक मामले युवा आबादी में हैं और इसके लक्षण 65 वर्ष की आयु से पहले ही दिखने लगते हैं।'

बेंगलूरु हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉ. सुहास वीपी के अनुसार 'बीमारी के चरण और देखभाल की जरूरत के अनुसार भारत में डिमेंशिया मरीज की देखभाल की लागत में व्यापक अंतर है। मूल परामर्श और दवाओं का मासिक खर्च करीब 2,000 से 5000 रुपये आता है। हालांकि शहरों में ऐसे मरीजों की घर में ही देखभाल समेत खर्च का दायरा 15,000 से 75,000 रुपये प्रति माह के बीच आता है। आधुनिक इलाज जिसमें एफडीए स्वीकृत दवा जैसे एडुकानुमाब का इस्तेमाल होने पर खर्च लाखों रुपये में पहुंच सकता है।'

भारत में डिमेंशिया के मरीज को देखभाल के दौरान कोलिनेस्टरेज और मेमनटाइन जैसी दवाओं की जरूरत होती है। इसके साथ गैर औषधीय विकल्प जैसे परामर्श से बेहतर सोच विकसित करने की चिकित्सा (कॉगनेटिव थेरेपी), व्यावहारिक हस्तक्षेप, रहन-सहन में मदद करना और देखभाल में सहायक कार्यक्रम शामिल हैं। मुंबई सेंट्रल के वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स के कंसलटेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत मखीजा ने बताया कि इसके उपचार में लक्षण प्रबंधन दवाएं (जैसे कोलेनिनेस्टेज इनहिबिटर), कॉगनेटिव थेरेपी, परामर्श और फिजियोथेरेपी जैसी सहायक देखभाल और उन्नत देखभाल विकल्प जैसे सहायक रहन-सहन सुविधाएं या डिमेंशिया केयर होम शामिल हैं।

कॉगनेटिव असेस्मेंट प्लेटफॉर्म डिमेंशिया इंडिया अलायंस डेमक्लीनिक मुफ्त मेमोरी स्क्रीनिंग के लिए टेलीमेडिसन, वर्चुअल डिमेंशिया आकलन, विशेषज्ञों से देखभाल और नैशनल डिमेंशिया सपोर्ट लाइन मुहैया कराता है। सुंदरम ने कहा, 'भारत में हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। डिमेंशिया के बढ़ते मामलों ने विशेषज्ञों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और समर्पित देखभाल बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर कर दिया है।'

मखीजा के अनुसार डिजेनरेटिव विकार के प्रमुख कारक बढ़ती आयु, परिवार में ऐसी बीमारी का होना, वंशानुगत स्थितियां, शिथिल जीवनशैली, खराब खानपान, मानसिक निष्क्रियता, सिर में चोट लगना, न्यूरोलॉजिकल विकार, मानसिक दबाव और नींद की कमी आदि हैं।

आर्टेमिस अस्पताल में न्यूरोलॉजी और मिर्गी के कंसल्टेंट डॉ. विवेक वरूण ने बताया, 'यदि इस रोगी की उचित ढंग से देखभाल नहीं की जाती है तो इससे बेहद गंभीर जटिलताएं उभर कर सामने आ सकती हैं। इनमें पूरी याददाश्त खोना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता खोना और बातचीत व अपनी बात समझाने की अक्षमता या प्रियजनों को पहचानने की विफलता आदि का होना आम बात है। बीमारी के अंतिम चरण में कई बार कुपोषण, संक्रमण और चलने-फिरने में परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा चलना-फिरना कम होने से रोग एस्पिरेशन निमोनिया और रक्त के थक्के भी जम सकते हैं। इस बीमारी का पहला पता चलने की स्थिति में कॉगनेटिव थेरेपी और जीवनशैली में बदलाव कर इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।'

सरकार ऐसे गैर संचारी रोगों के लिए नीतियां बना रही है और इन नीतियों में निजी अस्पताल और केंद्र भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में विशेष तौर पर बुजुर्गों की मानसिक देखभाल भी शामिल होती है, जो रोग के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने पर केंद्रित होती है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय डिमेंशिया देखभाल पहल की मदद करता है, जबकि सार्वजनिक-निजी साझेदारी कोष विशेषीकृत केंद्रों व शोध में मदद कर सकते हैं। आर्टेमिस अस्पताल के न्यूरोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. विवेक वरुण के अनुसार, 'इस रोग के उपचार में प्रगति निश्चित रूप से हो रही है। इस तरफ अबअधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस क्रम में नैशनल डिमेंशिया विशिष्ट नीतियां और समुदाय के स्तर पर पहल किए जाने की जरूरत है ताकि इन रोगों के बढ़ते दबाव से निपटा जा सके।'

www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा एपेक्स अकादमी, गांधीनगर, गुजरात निम्नलिखित सेवा अनुबंध प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित विक्रेता/ सेवा प्रदाताओ से GeM पोर्टल द्वारा दो बोली प्रणाली में मुहरबंद निविदा आमंत्रित करता है।
1) परिसर और सुविधा प्रबंधन सेवाए (हाउसकिपींग)
2) खानपान सेवाएँ
दोनों सेवाएँ बैंक के स्वामित्व वाले परिसर बड़ौदा एपेक्स अकादमी लॉ- गार्डन, अहमदाबाद, गुजरात के लिए अपेक्षित हैं।
''परिशिष्ट'' यदि कोई हो, तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा खंड में अधिसूचित किया जाएगा। बोलिकर्ता अंतिम रुप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख ले।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 13/01/2025 15:00 बजे तक।
अधिक जानकारी के लिये कृपया हमारी वेबसाइट : www.bankofbaroda.in/tenders/corporate-office पर जाए।
स्थान: गांधीनगर हेड
दिनांक: 20.12.2024 बड़ौदा एपेक्स अकादमी
96/24-25

www.bankofbaroda.in
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	निविदा का नाम	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1	डीसी, मुंबई और डीसी, हैदराबाद में निष्क्रिय और सक्रिय नेटवर्क घटकों की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए प्रस्ताव का अनुरोध	10 जनवरी 2025

विवरण बैंक की वेबसाइट: **www.bankofbaroda.in** पर निविदा अनुभाग, सीपीपीपी और सरकारी ई मार्केटप्लेस (GeM) पर उपलब्ध हैं।
यदि कोई परिशिष्ट होगा, GeM पोर्टल और बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा अनुभाग पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता इसे अवश्य देख लें।
स्थान : मुंबई
दिनांक : 20.12.2024 मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
(97/24-25)